सुर साधना

समाज में और प्रकृति के साथ सुर-ताल की साधना

ज्ञान मार्ग

सीमित वितरण **वाराणसी ज्ञान पंचायत की पहल** *अनियमितपत्रिका*

साईं वही ज्ञानी है, जो जाणे पर पीड़

अंक 10, जनवरी-मार्च 2026
सहयोग राशि रु. 10/-

इस अंक के बारे में

अमेरिका के आक्रामक तेवर साम्राज्यवाद के ढहने का संकेत करते नज़र आते हैं. रूस और चीन के दावे अब बहुध्रुवीय राजसत्ता के विचार के लिए जगह बना रहे हैं, जिसमें दुनिया को सभ्यतागत संप्रभुता के विचार से पुनर्संगठित करने की बात प्रमुख बन रही है.

सवाल यह है कि क्या युद्धों और राजसत्ताओं की निरंकुशता का इलाज सभ्यतागत संप्रभुता के विचार में है?

*इस अंक में इसी सवाल को केंद्र में रखते हुए बहुजन की **'वितरित सत्ता'** की परम्पराओं को उजागर करने से सम्बंधित रिचर्ड डेविड हेम्स का लेख है. ईरान पर आक्रमण के युद्ध की मौलिक बातों को उजागर करते हुए अविनाश और गिरीश के लेख और फ़िरोज़ खान की कविता हैं*

दुनिया में सत्य, न्याय और सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा के कार्य में बहुजन की पहल हेतु दिशाबोध के उद्देश्य से पिछले तीस वर्षों में हुए प्रमुख बदलाव और घटनाओं का एक संक्षेप में विवरण भी इस अंक में पेश किया गया है, जिसमें ज्ञान क्षेत्र में बदलाव के चलते साम्राज्यवादी राजनीति और बहुजन की पहल में हुए बदलावों को रेखांकित किया है.

आज जब कुछ शक्तिशाली देशों की नव रुढ़िवादी सत्ताएं सभ्यतागत बहुध्रुवीय व्यवस्थाओं के निर्माण की पेशकश कर रही हैं, उसमें बहुजन के लिए मौका बन रहा है कि वे 'वितरित सत्ता' के अपने समकालीन दर्शन को मज़बूती से सार्वजनिक चर्चा में ले आयें.

सम्पादकीय : युद्ध बनाम संवाद और सहयोग

युद्ध मनुष्य की सबसे निकृष्ट प्रवृत्तियों के संगठित हो जाने की घटना है. हम एक ऐसी दुनिया बनाने और उसमें रहने की उम्मीद करते हैं, जिसमें युद्ध की संभावनाएं न्यूनतम हों.

सदियों से बनारस भारत के बहुजन के जीवनमूल्यों का जीवंत नगर माना जाता रहा है. शिव की यह नगरी संवाद और सहयोग पर आधारित जीवन संगठन के विविध रूपों को मान्यता देती रही है. जीवन संगठन के ऐसे रूप ,जो किसी पर 'राज' करने की प्रेरणा से नहीं बनते, बल्कि **हर स्तर पर हर इकाई की 'स्वायत्तता' को रचनाशील व जीवंत बनाये रखने की प्रेरणा से बनते हैं. मनुष्य व समाज की भूमिका इससे तय होती है. यह विचार 'शिव' है.** ऐसे नैतिक जीवन संगठन के प्राण 'स्वायत्तता' में बसते है. विविध समाजों और समुदायों की स्वायत्तता स्वीकारने का मतलब बराबरी का सम्मान और परस्पर संवाद की अनिवार्यता. यहाँ 'युद्ध' नहीं परस्पर सहयोग को वरीयता मिलती है. बनारस को इन विचारों को पुनर्स्थापित करने में आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभानी है.

21वीं सदी को संवाद और संपर्क की दुनिया घोषित किया जाता रहा है. लेकिन इसकी घोषणा करने वाले 'युद्धों' के बल पर ही 'राज' करने की नीतियाँ अपना रहे हैं. भारत हो या अमेरिका, रूस हो या चीन. इन देशों के सत्ताधारी नेताओं की भाषा और व्यवहार 'सभ्य' शब्द के घेरे से बाहर हैं.

2026 वर्ष की शुरुआत ही अमेरिका के द्वारा वेनेज़ुएला, क्यूबा, ईरान आदि देशों को धमकी देने से हुई है, वेनेज़ुएला के सर्वोच्च पदाधिकारी और उनकी पत्नी का अपहरण कर अमेरिका ने खुद के असभ्य होने का परिचय दिया है. पिछले लगभग सौ सालों में बनी दुनिया की व्यवस्थाओं को उध्वस्त कर अमेरिका ने इज़राइल के सहयोग से ईरान पर आक्रमण कर दिया.

अमेरिका का इतिहास अपने ही देश के लोगों पर और दुनिया के तमाम देशों पर आक्रमण का और जनसंहार करने का रहा है. आश्चर्य यह कि फिर भी इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता रहा है !

सुर साधना का यह अंक तैयार करने तक स्थिति यह है कि युद्ध जारी है लेकिन अमेरिका और इज़राइल के हौसले पस्त होने के संकेत आने लगे हैं. वास्तव में क्या होगा ये निश्चित कहा तो नहीं जा सकता लेकिन यह बात तय है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी अंतरर्राष्ट्रीय कानून, संस्थाए और व्यवस्थाएं बनी थीं वे निष्क्रिय हो गई हैं. केवल इतना ही नहीं, बल्कि उन सभी विचारों, अवधारणाओं, दर्शन, सिद्धांत, लक्ष्य, मूल्य आदि पर प्रश्नचिन्ह लग गए हैं, जिन्हें मनुष्य और देश के लिए प्रगतिशील माना जाता रहा. पूँजी व साइंस के संयुक्त बल से यूरोप से प्रसारित सत्ता सम्बंधित विचार, यानि पुनर्जागरण व प्रबोधन तथा फ़्रांसीसी क्रांति के विचार, साम्राज्यवादी राजनीति को बल देने वाले साबित हुए. अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की रूढ़िवादी-नव-साम्राज्यवादी सत्ताएं दुनिया पर राज करने के लिए 21वीं सदी में वित्तीय पूँजी और कृत्रिम बुद्धि के बल पर नए विचार और व्यवस्थाओं को गढ़ रही हैं.

यह निश्चित है कि साम्राज्यवाद के किन्हीं भी रूपों में बहुजन का उत्पीडन बढ़ना है. **पूरे समाज, देश, दुनिया और प्रकृति की भलाई बहुजन की पहल से 'वितरित स्वायत्त सत्ता' के समकालीन रूपों में ही हो सकती है.** इसके लिए बराबरी की शर्त पर परस्पर सम्मानपूर्ण संवाद और सहयोग के मज़बूत धागों को बुनने की आवश्यकता है.

वाराणसी के बहुजन में हलचल

-सुर साधना संयोजन समूह

वाराणसी में सरकारी नीति और तंत्र के खिलाफ बहुजन में व्यापक रोष व्याप्त है. सरकारी तंत्र ने वाराणसी नगर को पर्यटन का स्थान बनाने में नगर निवासियों के खिलाफ अभियान सा छेड़ रखा है. इस क्रम में नगर के चारों तरफ बड़े पैमाने पर किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है और शहर के अन्दर अनेक मोहल्लों और बाज़ारों पर बुलडोज़र चलाकर टूरिस्टों के लायक सुविधाएँ और मनोरंजन के स्थान बनाने की तैयारी है. इसके चलते नगर का कारीगर समाज, पटरी-ठेले के दुकानदार, छोटी पूँजी के उद्यमों से जुड़े कारोबारी और मज़दूरों के परिवार, सभी प्रभावित हो रहे हैं. वाराणसी जिले की आबादी का लगभग 90 फीसदी इनसे ही बना है और नगर का स्वभाव और संस्कृति इन्हीं परिवारों के बल पर गढ़ी हुई है. वाराणसी जिले में मज़दूरों की एक बड़ी संख्या है और हाल ही में श्रमिक कनून में किये गए संशोधनों के चलते मज़दूर संगठनों में व्यापक असंतोष है. स्त्रियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं से नगरवासियों की चिंता बढ़ती जा रही है.

नगर में चार विश्वविद्यालय और अनेक महाविद्यालय हैं. इनमें पढ़ने वाले छात्र भी बहुजन समाज के ही अधिक हैं, लेकिन इनके पक्ष में न सरकार की नीतियाँ है, न प्रशासन और न ही अध्यापकगण. हाल ही में यूजीसी की नई नियमावली को लागू करने के सवाल पर जाति के नाम पर छात्रों में फूट डालने की नीति खुलकर सामने आई है और आम छात्रों में इसके प्रति रोष है.

बहुजन में व्याप्त इस रोष और असंतोष के समाधान का एक रास्ता बहुजन के बीच आपसी संवाद को बढ़ाने से निकल सकता है. संवाद के ऐसे अनेक मंच और स्थान बनाने में सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा, जहाँ विविध विचारों का बराबरी से सम्मान होना अनिवार्य शर्त हो. विचारों की प्रासंगिकता पर गहन संवाद के साथ उनके समकालीन नवीनीकरण की क्रिया को प्रोत्साहित करना होगा. **सौ सालों से संगठित विचारों की चौखट से बाहर आने और बहुजन की शक्तियों के नवीनीकरण के रास्तों की खोज में लगना होगा. ज्ञान के हर क्षेत्र में मनुष्य की सक्रियता की प्रेरणाओं व प्रकारों की मीमांसा हो, और बहुजन के नए आख्यान आकार लें.**

बहुजन की एकता का विचार

-फ़ज़लुर्रहमान अंसारी

इस समय जाति के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में जो भेदभाव हो रहा है, वो किसी भी स्तर से ठीक नहीं है. इस भेदभाव के खिलाफ़ छात्र संगठनों एव छात्रों के द्वारा लगातार आंदोलन चल रहा है. हम कारीगर समाज के लोग उसका पूरा समर्थन करते हैं.

साथ ही उन छात्र संगठनों से एव छात्रों से भी कारीगर समाज ये अपील करता है कि कारीगर समाज के मौलिक ज्ञान के साथ भी हो रहे भेदभाव के खिलाफ़ आप भी हमारा साथ दें. तभी हमारी एकता यानी बहुजन की एकता मजबूत होगी.

अमरीका के द्वारा भारत पर 18%टेक्स लगाने से सबसे ज़्यादा प्रभावित बहुजन समाज के लोग ही होंगे. कारीगर किसान बहुजन समाज का अभिन्न अंग हैं और इनके उत्पादनों और उत्पादित वस्तुओं पर अमरीकी सरकार 18%टैरिफ लेगी और अमेरिका की उत्पादित वस्तुओं को 0% टैरिफ पर भारत को देगी. इससे किसान और कारीगर समाजों के लिए अमरीका में बाज़ार ही खत्म हो जाएगा और अमरीकी वस्तुओं के लिए भारत में बाज़ार खोल देने से हमारा किसान और कारीगर समाज पूरी तरह टूट जाएगा. बहुजन की एकता के प्रयास में ही भविष्य है.

•

मार्च का महीना और बहुजन के नवसृजन के उत्सव

इस बार मार्च का महीना बहुजन की अनेक परम्पराओं के पर्वों को लेकर आया. वसंत ऋतु के बाद, होली का पर्व 3-4 मार्च को नव सृजन की प्रेरणा के विविध रस और रंगों से भरा उत्तर भारत में नव वर्ष के आगमन की घोषणा लेकर आया. इसी माह में 19 मार्च को नगर के दक्षिण भारतीयों में नए साल के आरम्भ के रूप में 'गुडीपाडवा' और 'उगादी' के नाम से मनाया गया. विविध सरकारी और स्वयं सेवी संस्थाओं में 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्त्री दिवस के नाम से मनाया गया. रमजान के महीने का समापन तथा ईद का पर्व 21 मार्च को और 19 मार्च से 26 मार्च चैत्र नवरात्रि के पर्व रहे और रामनवमी भी. इनके अलावा महान स्त्री और पुरुषों के स्मृति दिवस मनाये गए,

आज राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्वों को मनाने की होड़ क्या साम्राज्यवादी भाव, मूल्य और प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं? क्या ये सामान्य जन की सृजन क्षमता को नष्ट कर स्थानीय ज्ञान को नकार कर, उन्हें बाहरी बाज़ार पर अधिकाधिक निर्भर बनाने के उद्यम हैं? क्या इनके आज के रूप संगठित धर्म और राष्ट्रवाद के विचार और सत्ता से प्रभावित हैं?

आज ये पर्व जिस तरह से मनाये जाते हैं, क्या ये हमारे देश के बहुजन की संस्कृति के प्रतीक कहे जा सकते हैं? इन सवालों पर चिंतन की आवश्यकता है.

नई दुनिया गढ़ने का सरल तरीका

रिचर्ड डेविड हेम्स (Richard David Hames), 1 फरवरी 2026

https://richarddavidhames.substack.com/p/global-governance-20

शासन की वितरित सत्ता की आवश्यकता और इसके उदहारण

*बहुजन स्वराज पंचायत साम्राज्यवादी सत्ता का मुकाबला '**वितरित सत्ता**' के निर्माण में देखती है न कि विकेन्द्रित सत्ता के निर्माण में. वर्ष 2022 में विद्या आश्रम से प्रकाशित पुस्तक 'स्वराज परम्पराएँ' में भारत के बहुजन में व्याप्त 'वितरित सत्ता' के दर्शन, जीवनमूल्य और संगठन की परम्पराओं का संकलन है. प्रस्तुत लेख रिचर्ड डेविड हेम्स ने फरवरी 2026 में लिखा है, जो दुनिया के बहुजन में व्याप्त 'वितरित सत्ता' के उदहारण प्रस्तुत करते हुए इसकी आवश्यकता को रेखांकित करता है. सत्य, न्याय और भाईचारे पर आधारित दुनिया बनाने की दिशाबोध के लिए सामाजिक परिवर्तन के कार्यकर्ताओं को 'वितरित सत्ता' के विमर्श को सार्वजनिक दुनिया में लाना होगा.*

सुर साधना में प्रकाशन के लिए लेखक रिचर्ड डेविड हेम्स की सहमति से उनके सबस्टेक से लिया गया यह लेख गिरीश सहस्रबुद्धे द्वारा हिंदी में अनुवादित है. **-संपादक**

जैसे-जैसे दुनिया की व्यवस्थाओं पर अमेरिका का वर्चस्व घटता जाता है, वैश्विक शासन की कहानी तेजी से बदलती जाती है. इस बदलाव में हमारे लिए एक ऐसी दुनिया के लिए नये रास्ते खोजने की पुकार है, जिसकी पहचान तेज़ी से बहुध्रुवीय (मल्टीपोलर) होती जा रही है. **साम्राज्यवाद के दबदबे का टूटना, हमें पारंपरिक पश्चिमी मॉडल से आगे देखने और दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे परे के समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने-बाने से प्रेरणा लेने की चुनौती देती है.**

दुनिया के बहुध्रुवीय (मल्टीपोलर) भविष्य में संक्रमण को मात्र सत्ता संबंधों की गति (पावर डायनामिक्स) में बदलाव के रूप में आंकना सही नहीं होगा. बल्कि इसे दुनिया भर से विविध किस्म के शासन प्रकारों के उदाहरणों का इस्तेमाल कर एक विकेन्द्रित और सहयोग-आधारित वैश्विक शासन की कल्पना करने की चुनौती के रूप में भी देखना होगा. जैसे-जैसे वैश्विक सत्ता ज़्यादा बिखरती है, ऐसी व्यवस्थाओं की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, जो जटिलताओं का प्रबंधन कर सकें और साथ ही अधिपत्य और आक्रामकता से मुक्त परस्पर सहयोग को आसान बना सकें.

अफ्रीकी महाद्वीप पर *'अफ्रीकन यूनियन'* क्षेत्रीय क्षमता और सामूहिक क्रिया का एक प्रतीक है. दक्षिण-पूर्व एशिया की ऐतिहासिक ***'मण्डल व्यवस्था'*** की तरह, अफ्रीकन यूनियन कई तरह के ऐसे देशों को जोड़ता है जिन सब की अपनी-अपनी खास संस्कृति, भाषा और राजनीतिक प्रणाली है. आपसी संवाद और साझा मकसद के ज़रिए यूनियन इनमें आपसी सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देता है. अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जैसी पहलें व्यापार की रुकावटों को हटाते हुए परस्पर आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय एकता की ताकत बढाने के उदाहरण हैं. किसी भी तरह के तानाशाही निरीक्षक, या दण्डात्मक व्यवस्था की ज़रूरत के बिना ये पहलें न सिर्फ़ आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि राजनीतिक संबंधों और सांस्कृतिक लेन-देन को भी मज़बूत करती हैं. इससे अफ्रीकी देशों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा मिलता है, और महाद्वीप के उपनिवेशवाद के बंधन से आज़ाद होने की कोशिशों में मदद होती है. ***'मण्डल व्यवस्था'*** में परिवर्तनशील भौगोलिक सीमाएं और अतिव्यापी प्रभाव-क्षेत्रों का आग्रह निहित है. अफ्रीकन यूनियन की "विविधता के बीच एकता बनाए रखने की क्षमता" में इस आग्रह का एक आधुनिक प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है.

इसी तरह, दक्षिण अमेरिका में, '***मर्कोसुर***'—जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं—आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय गठबंधनों की ताकत का महत्व दर्शाता है. यह गठबंधन इस बात को उजागर करता है कि अगर देश साथ मिलकर पूरे इलाके को फ़ायदा दिला सकने वाले फ़ैसले लेते हैं तो अपनी संप्रभुता कैसे बनाए रख सकते हैं. आपसी व्यापार को बढ़ावा देकर और साझा चुनौतियों का सामना करके, मर्कोसुर इलाके के ताने-बाने को जिस प्रकार से मज़बूत करता है, वह दक्षिण-पूर्व एशिया के उस 'मल्टीप्लेक्स ऑर्डर' की याद दिलाता है, जहाँ ताकत कई इकाइयों के बीच बँटी और साझा होती थी. ऐसे इंतज़ाम सहयोगात्मक संप्रभुता की संभावना को उजागर करते हैं, जहाँ देश अपनी स्वायत्तता बरकरार रखते हुए सामूहिक ताकत का फ़ायदा भी उठा सकते हैं.

***'आर्क्टिक काउंसिल'* शासन के ऐसे मॉडल का एक अनपेक्षित लेकिन ज़बरदस्त उदाहरण है, जिसमें न सदस्यों के बीच कोई ऊँच-नीच है और न उनपर कोई बाहरी दबाव .** आठ आर्क्टिक देशों से मिलकर बनी यह बॉडी आर्क्टिक इलाके में पर्यावरण सुरक्षा और टिकाऊ विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करती है. भौगोलिक राजनीति के बावजूद, काउंसिल आम सहमति और सहयोग के सिद्धांतों पर काम करती है,

जिसमें आदिवासी समुदाय और गैर- आर्क्टिक देश पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल होते हैं. यह सबको साथ लेकर चलने वाला नज़रिया दक्षिण-पूर्व एशिया के 'साझा स्थानों और परस्पर संवाद पर आधारित जीवनशैली' की उस मिसाल जैसा है, जहाँ अलग-अलग हितधारक (स्टेकहोल्डर) मिलकर संसाधनों के इस्तेमाल का प्रबंधन करते हैं और साझा चुनौतियों का सामना करते हैं. *आर्क्टिक काउंसिल* की सफलता उन इलाकों में सहयोग के मूल्य को दिखाती है, जहाँ आम शासन मॉडल कम असरदार हो सकते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल दुनिया में भी हमारे लिए सबक हैं. विकेन्द्रित ब्लॉकचेन तकनीकी के बढ़ने से पारंपरिक सत्ता के ढांचे (पावर स्ट्रक्चर) को चुनौती मिल रही है, जिससे पीयर-टू-पीयर नेटवर्क बिना किसी केन्द्रीय प्राधिकरण के काम कर सकते हैं. बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी, जो अपने-अपने समुदायों द्वारा नियंत्रित होती हैं, यह दिखाती हैं कि वितरित प्रणाली के ज़रिए कैसे भरोसा और स्थिरता बनाए रखी जा सकती है. यह तकनीकी विकास मण्डल तर्क जैसा है, जहाँ अधिकार केंद्रीकृत नियंत्रण के बजाय सामूहिक भागीदारी से मिलता है. जैसे-जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, यह शासन प्रणाली का एक ऐसा रूप दर्शाती है, जो ज़्यादा पारदर्शी, न्यायपूर्ण और मज़बूत है. पारंपरिक ऊंच-नीच को दरकिनार करके, ब्लॉकचेन यह दिखाता है कि कैसे विकेन्द्रित टेक्नोलॉजी समुदाय को मज़बूत बना सकती हैं.

दक्षिण-पूर्व एशिया की *'मण्डल व्यवस्था'*, जो 5वीं से 15वीं सदी तक आम थी, शासन पद्धति का एक दिलचस्प ऐतिहासिक मॉडल देती है, जो आज के तरीकों के लिए सीख बन सकता है. केन्द्रीयकरण वाले पावर स्ट्रक्चर के उलट, 'मण्डल व्यवस्था' में वितरित सत्ता थी, जिसमें प्रभाव के क्षेत्र एक-दूसरे में मिले हुआ करते थे. सत्ता स्थानीय अधिकार क्षेत्रों में बंटी हुई थी, और सीमाएँ बदलती रहती थीं, जिससे गठबंधनों और सांस्कृतिक लेन-देन के ज़रिए एक गतिशील राजनीतिक माहौल बना रहता था. सहयोग करने की यह क्षमता और यह लचीलापन दिखाता है कि कैसे अलग-अलग संस्थाएं शांति से एक साथ रह सकती हैं, जो एक बार फिर ग्लोबल गवर्नेंस में लचीलापन और सहयोग की अहमियत पर ज़ोर देता है. यह मॉडल हमें फिर यह सोचने के लिए उकसाता है कि सत्ता कैसे साझा की जा सकती है और स्वायत्तता से समझौता किए बिना सहयोग कैसे हासिल किया जा सकता है.

***'पेरिस एग्रीमेंट'* अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते पर है यह नहीं कहा जा सकता. लेकिन इस एग्रीमेंट ने भी लगभग सभी की भागीदारी को बढ़ावा दिया और यह शायद अभी भी ग्लोबल चुनौतियों से निपटने में बहुकेन्द्रित सहयोग (पॉलीसेंट्रिक कोऑर्डिनेशन) की ताकत का सबूत है.** लगभग 200 देशों के जलवायु परिवर्तन से निपटने के वादे के साथ, यह संधि दिखाती है कि राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और मिलकर काम करने वाले चौखट के ज़रिए ग्लोबल मुद्दों से कैसे निपटा जा सकता है. एग्रीमेंट की सफलता उन आम, लेकिन हर देश के लिए कमोबेश अलग-अलग, ज़िम्मेदारियों को निभाने के सिद्धांत पर निर्भर करती है, जिसमें हर देश की अपनी अलग क्षमताओं और योगदान को माना जाता है – यह अवधारणा दक्षिण-पूर्व एशिया के (मण्डलों के) विविध राज्यतंत्रों के बीच के ऐतिहासिक तालमेल की याद दिलाता है. यह तरीका साझा ज़िम्मेदारी और जवाबदेही की भावना प्रेरित करता है, जिससे देशों को एक आम लक्ष्य की ओर मिलकर काम करने के लिए बढ़ावा मिलता है. पेरिस एग्रीमेंट इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे साझा लक्ष्यों और अलग-अलग रास्तों से वैश्विक सहयोग हासिल किया जा सकता है, कम से कम तब जब हमें इसकी पर्याप्त चाह हो.

इल्या प्रिगोजीन की "आन्तरिक तालमेल के टापू" ("islands of coherence") की अवधारणा मल्टीपोलर दुनिया में ग्लोबल गवर्नेंस को समझने के लिए एक और नज़रिया देती है. किसी भी जटिल परिवेश में, ये टापू अव्यवस्था के माहौल में उभरे व्यवस्थित स्थानों से हैं. इस विचार को वैश्विक शासन पर लागू करने से पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी, स्थानीय इलाके या "गांव जैसे" नेटवर्क अंदरूनी स्थिरता और तालमेल का चरम हासिल कर सकते हैं. ये इलाके, अफ्रीकन यूनियन या मर्कोसुर की तरह, अपने बृहत् सन्दर्भ में असरदार तरीके से काम करते हैं, यह दिखाते हुए कि कैसे विकेन्द्रित शासन (डीसेंट्रलाइज़्ड गवर्नेंस) लचीलेपन और तालमेल (एडैप्टेबिलिटी) को बढ़ावा दे सकता है. तालमेल के ये टापू इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे एक जटिल दुनिया में स्थिरता अपने आप उभर सकती है, जो गवर्नेंस के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट पेश करती है, जो लचीला और अनुकरणीय दोनों हो.

तालमेल के टापू नवीनीकरण और सहयोग के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं. इसके साथ ही वे ऐसे केन्द्रों के तौर पर काम कर सकते हैं जहाँ नए विचारों और और समस्या के समाधानों को परखा जा सके. यह गति दक्षिण-पूर्व एशिया की उस ऐतिहासिक मण्डल प्रणाली को प्रतिबिंबित करती है, जहाँ वितरित सत्ता और साझा प्रभाव वाले क्षेत्रों ने लचीलेपन और स्थानीय ज़रूरतों के प्रति सजगता की संभावना पैदा की. इन टापुओं को बढ़ावा देकर, एक वैश्विक शासन का जाल बन सकता है, जिसकी खासियत अलग-अलग सांस्कृतिक समूहों के एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश में न होकर परस्पर सम्मान के साथ मिलकर काम करने में है. नवाचार के ये केंद्र ऐसे माहौल को,

जिसमें विविध विचार पनप और फैल सकते हैं, बनाते हुए खुशहाली को बढ़ावा दे सकते हैं.

प्रिगोजिन की अवधारणा को वैश्विक शासन में शामिल करना बहुलवाद और विविधता को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है. प्रिगोजिन के टापू एक एकजुट, सुसंगत, फिर भी विविधतापूर्ण अंतरराष्ट्रीय विश्व-व्यवस्था के लिए आधारशिला के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो सह-अस्तित्व के लिए अनेक दृष्टिकोणों और तरीकों को प्रोत्साहित करते हैं. यह विविधता कठोरता को रोक कर और समस्याओं के रचनात्मक समाधान को बढ़ावा दे कर इस मॉडल की समग्र ताकत को बढ़ाती है. सुसंगति के इन टापुओं को जोड़कर और उनमें तालमेल बैठा कर हम एक ऐसी अधिक स्थिर, लचीली और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं, जो 21वीं सदी की जटिलताओं के प्रति उत्तरदायी हो. ऐसा करने में, हम एक ऐसी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करते हैं जहाँ सहयोग और विविधता वैश्विक स्थिरता की आधारशिला हैं.

यहाँ चर्चित सारे उदाहरण ऐसे बहुरूपी विश्व की संभावना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें स्थिरता और खुशहाली परस्परावलंबन और एक दूसरे के प्रति आदर की बिना पर हासिल होती है, न कि अधिपत्य और आक्रामकता की बिना पर. यह कतई जरूरी नहीं कि दुनिया में अमेरिका के प्रभाव का ह्रास अराजक ही बरपाए. यह ह्रास तो एक ऐसी विश्व – प्रणाली को अपनाने का मौका देता है, जहाँ अधिकार साझा किए जाते हैं, वैविध्यपूर्ण ताने-बाने एक-दूसरे में शिरकत करते हैं, युद्धखोरी का खात्मा होता है, और विविध मूल्य-व्यवस्थाएं सामंजस्य के साथ जीती हैं. दक्षिण पूर्व एशियाई मॉडल और अन्य क्षेत्रीय प्रणालियों से सीख लेकर हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो—एक ऐसी विश्व-दृष्टि पर टिकी वैश्विक प्रणाली, जिसमें इतिहास के सबक एक टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में हमारा मार्गदर्शन करें.

इस तरह से नए सिरे से सोचा गया वैश्विक शासन का ढांचा अलग-अलग समुदायों की ज़रूरतों और उम्मीदों के प्रति ज़्यादा ज़िम्मेदार होने का विश्वास दिलाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज़्यादा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया बने. इन अलग-अलग मॉडलों का इस्तेमाल करके, हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ टकराव नहीं, बल्कि सहयोग हमारे साझा भविष्य को आकार देगा.

हालांकि यह भविष्य की एक सम्मोहक परिकल्पना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा ताकतें ऐसे बदलाव को अपना सकती हैं. ऐतिहासिक अनुभव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो प्रस्थापित ताकतें अक्सर बदलाव के खिलाफ रही हैं, खासकर जब इसमें नियंत्रण त्यागना या अधिकार बांटना अनिवार्य हो. ऐसे सम्राटों, अमीरों और तानाशाहों को जिनके निहित हितों को आज तक तानाशाही प्रणालियों में संजोया गया हो, ऐसी दुनिया में ढल पाना बहुत मुश्किल लग सकता है, जहाँ सत्ता का बंटवारा ज़्यादा समतल हो. इसके अलावा, यह भी तय है कि भू-राजनैतिक टकराव और राष्ट्र-केन्द्रित हितों की चाह बेशक आपसी सम्मान को बढ़ावा देने की कोशिशों को और भी पेचीदा बना देती है.

जब हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो एक-दूसरे पर निर्भरता, विविधता और दखल न देने पर आधारित हो, तो इन चुनौतियों की, और इस तरह के बुनियादी बदलाव को पूरी तरह अपनाने में मौजूदा सत्ता केन्द्रों की संभावित हिचकिचाहट की पहचान और उसका स्वीकार दोनों ज़रूरी है. **इस चिंतन में निहित अनिश्चितता हमें इस बारे में सतत सजग रखती है कि एक तरफ जहाँ अधिक न्याय-दायी वैश्विक व्यवस्था मुमकिन है, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए ठोस प्रयास, संयम और विवेक से युक्त संवाद तथा सत्ता के पुराने घिसे-पिटे गलियारों से मुक्त होने की इच्छा की नितांत ज़रूरत है** ताकि बढती रफ़्तार से जुड़ती जाती इस दुनिया में सहयोग और सह-अस्तित्व के नए रास्ते खोजे और रचे जा सकें.

बहुजन की पहल को आकार कैसे मिले? विचार और चिंतन के लिए कुछ बिंदु

- बहुजन की राजनीति में केन्द्रीय सत्ता का स्थान गौण है. वास्तव में केन्द्रीय सत्ता को मान्यता मिलना 'राजनीति' को जन्म देती है. बहुजन की 'राजनीति' नहीं होती. बहुजन की व्यवस्था में सत्ता के अनेक केंद्र होते हैं, जो आपस में सहयोग के आधार पर सामाजिक ताना-बाना बनाते हैं. इस ताने-बाने के जाल को हमारे देश में 'स्वराज' कहा जाता रहा है, जिसमें 'समाज' की ताकत को 'राज्य' की ताकत की तुलना में वरीयता मिलती है और यह पंचायतों के मार्फ़त रूप लेती है. समय और स्थान के अनुसार इन पंचायतों के रूप तय होते रहे हैं.
- बहुजन में ज्ञान की किसी भी एक धारा को सर्वोच्च स्थान नहीं मिलता, बल्कि समाज में स्थित विविध ज्ञान धाराओं के सहयोग और सम्बन्ध पर जोर रहता है.
- बहुजन में 'युद्ध' यह कोई हल नहीं माना जाता और न ही यह शौर्य का प्रतीक है. बहुजन में समस्याओं के हल के लिए संवाद को सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है और समस्या का हल निकालने तक इसे बनाये रखने का आग्रह रखा जाता है. पंचायत इस तरीके और आग्रह को मूर्त रूप देने की विधा है.

समाज परिवर्तन की दिशा की खोज में पिछले 30 वर्षों का संक्षेप में ब्यौरा
चिंतन और संवाद के लिए

नीचे दिए गए टेबल में पिछले 30 वर्षों में ज्ञान-क्षेत्र के साथ कुछ प्रमुख घटनाओं और साम्राज्यवादी राजनीति में आये प्रमुख बदलावों को दर्शाने की कोशिश है. इन बदलावों के चलते इस अवधि में बहुजन (सामान्य जन) द्वारा ली गई पहल को भी दर्शाया है. हम चाहते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में जो बदलाव आते चले गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्त्ता बहुजन के लिए, बहुजन की पहल पर एक बेहतर दुनिया को बनाने की संभावना का रास्ता बनाने की ओर बढ़ें. यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी राजनीति में बहुजन को कोई जगह नहीं होती है. ध्यान देने की बात यह है कि इन बदलावों के चलते बहुजन को अपने लिए अपने ज्ञान के बल पर समाज संगठन के दर्शन, विचार और कार्य को गढ़ने के मौके बन चुके हैं, इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता नज़रंदाज़ न होने दें.

वर्ष-अवधि	ज्ञान	प्रमुख घटनाएँ/प्रक्रियाएं	साम्राज्यवादी राजनीति	बहुजन (सामान्य जन) की पहल
1990-2000	ज्ञान के क्षेत्र में साइंस को शीर्ष स्थान से हटाकर उसके स्थान पर सूचना-साइंस (कंप्यूटर-इन्टरनेट) का दबदबा स्थापित होना शुरू हुआ.	• वैश्वीकरण (1990), विश्व व्यापार संगठन (1994), अगले दस साल में छोटे और कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षण ख़त्म हुआ. • ट्रेड यूनियन आन्दोलन टूटे. • बहुराष्ट्रीय कंपनियों का फैलना. वित्तीय व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव. • तकनीकी क्षेत्र में जापान की बराबर की स्थिति का टूटना और अमेरिका का फिर से कब्ज़ा.	• सोवियत संघ का टूटना • साम्राज्यवादी राजनीति में अमेरिका का दबदबा और बढ़ गया. • इराक पर अमेरिका का आक्रमण (पहला खाड़ी युद्ध 1991)	• विस्थापन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ अनेक आन्दोलन हुए. • भारत में **सामाजिक न्याय आन्दोलन** के तहत ओबीसी के लिए आरक्षण हासिल हुआ. • **जल, जंगल और ज़मीन के आन्दोलनों** ने बहुजन के अधिकार और पर्यावरण विनाश के मुद्दों पर देश भर में संघर्ष किये तथा बड़े और छोटे आन्दोलनों को एकता के धागे में पिरोया. विकास को विनाश घोषित किया. • उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन नई ऊँचाइयों पर गया.
2000-2010	• सूचना-साइंस का ज्ञान शीर्ष पर पहुंचा. • नतीजे स्वरुप पिछले 2-4 सदियों से स्थापित यूरोपीय दार्शनिक व वैचारिक ढांचे पर संकट के बादल. • साइंस के दृष्टिकोण को चुनौती मिली. • बोलीविया और इक्वाडोर देशों में देशज ज्ञान (लोकविद्या) के बल पर देश का संविधान और	• अरब स्प्रिंग के नाम से कई अरब देशों में भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ आन्दोलन हुए. मिलते-जुलते घटना क्रम इटली, ग्रीस, भारत और इंडोनेशिया में भी हुए. यह एक पेचीदी प्रक्रिया रही और कोई नए विचार नहीं आये. • राजसत्ताओं के अधिकाधिक अनैतिक, निरंकुश और असंवैधानिक व्यवहार बढ़ते चले गए. • चीन का एक महाशक्ति बन जाना.	• लोकविद्या के बल पर बन रहे उत्पादों को बाज़ार में सस्ते में ले आने की होड़. किसान, कारीगर, स्त्रियोंआदिवासियों के ज्ञान की लूट के तंत्र का तेज़ी से विकास. • अमेरिका का अफगानिस्तान पर और फिर इराक़ (दूसरा खाड़ी युद्ध 2003) पर आक्रमण • इस्लामिक देशों पर केन्द्रित आक्रमण और 'आतंकवाद' के नाम से वैश्विक दुश्मन की पहचान. • संगठित सांप्रदायिक दंगों और जनसंहार का नया दौर शुरू हुआ. • BRICS का बनना	• विस्थापन का दौर अधिक तेज़ हुआ. आदिवासियों, छोटे व्यवसाइयों और किसानों को विस्थापित करके नए उद्योगों के लिए ज़मीनों और बाज़ार पर कब्ज़ा. असंख्य स्थानीय संघर्ष हुए. • **'एक दूसरी बेहतर दुनिया संभव है'** के नारे के साथ विश्व सामाजिक मंच का बनना. 2004 मुम्बई में विश्व सामाजिक मंच का आयोजन. बौद्धिक सत्याग्रह का पहला ऐलान. • अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन (वाया कम्पेसिना) द्वारा **'खाद्य संप्रभुता'** का विचार आया. • **यूरोप, अमेरिका और कनाडा के छात्र आन्दोलन.** कारखानों के संघर्ष का विश्वविद्यालयों में स्थानांतरण जीवंत ज्ञान के आधार पर बौद्धिक पूँजीवाद को

	शासन बनाने के प्रयास हुए.		• अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर अमेरिका का लगभग एकाधिकार.	चुनौती. जिंदा और मृत ज्ञान, स्वसंगठन और स्वशिक्षा के विचारों को नया महत्त्व मिला. • बोलीविया और इक्वाडोर में नए किस्म के बहिष्कृत समाज के आन्दोलन, ‘**धरती माँ के अधिकार**’ और ‘**प्लुरिनेशनल स्टेट**’ के विचारों के इर्द गिर्द नई राजनीतिक संरचना का उदय जिसमें स्वायत्तता और प्रादेशिक सांस्कृतिक चेतना को विशेष स्थान.
2010-2020	• सत्य की स्थापित अवधारणा में बदलाव (पोस्ट ट्रुथ) और मीडिया व बाज़ार का सीधा दखल • विविध सभ्यता तथा संस्कृतियों के आख्यानों का महत्त्व बढ़ना.	• 2014 से नव-रुढ़िवादियों का उदय. दुनिया के कई देशों में इनकी सरकारें बनीं. • डेमोक्रेसी के नाम से चल रही राजसत्ता के प्रकार बहुजन के पक्ष में नहीं हो सकते यह साफ़ हो चला. • समाजवाद की धारा भी डेमोक्रेसी के विचारों की हमकदम होकर परिवर्तनकारी शक्ति तेज़ी से खोती चली गई.	• चीन की ताकत बढ़ते जाना. • कोविड महामारी के दौरान भारत और शक्तिशाली देशों ने राजसत्ता और उसकी सभी (प्रशासनिक, न्यायिक, शिक्षा-चिकित्सा, वित्तीय, बाज़ार आदि) व्यवस्थाओं को बड़े पैमाने पर पुनर्संगठित किया और बहुजन को इनसे बाहर किया. • नव रूढ़िवाद की राजनीति का विस्तार	• अमेरिका में बहुजनों का ‘**हम 99 फीसदी हैं**’ के नारे के साथ राष्ट्र की संपदा के अत्यंत गैर-बराबर बंटवारे के खिलाफ आन्दोलन. • भारत में **किसान आन्दोलन** बहुजन का एक बहुत बड़ा आन्दोलन बनकर उभरा और इसने न केवल राजसत्ता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को झुकाने का दम दिखाया. कृषि क्षेत्र में काले कानूनों को वापस लेने और पक्षपातपूर्ण समझौतों को ख़ारिज करने की मांग से शुरू हुए इस आन्दोलन ने बहुजन के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया. न्याय, त्याग और भाईचारे के बल पर बहुजन समाज को पुनर्संगठित करने की दिशा का बोध कराया.
2020-2025	• कृत्रिम बुद्धि का ज्ञान के क्षेत्र पर तेज़ी से एकाधिकार की ओर बढ़ना. • ‘सभ्यतागत ज्ञान’ और उसके फैलाव के क्षेत्रों पर दावा.	• रूस का युक्रेन पर आक्रमण और पश्चिम के देशों (यूरोप और अमेरिका) द्वारा पिछले दो सौ वर्षों में दुनिया में किये गए जनसंहारों और युद्धों के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा करना . • इस्लामिक देशों की एकता में बिखराव • फिलिस्तीन में इज़राइल द्वारा जनसंहार	• अमेरिका को रूस और चीन की खुली चुनौती. • बहुध्रुवीय सत्ता की राजनीति का आगाज़. अमेरिका, रशिया, चीन बने बड़े खिलाडी. • भारत में, जाति, धर्म और SIR जैसे मुद्दों पर राजनीति में उठाव.	• विद्या आश्रम, सारनाथ, वाराणसी से बहुजन स्वराज पंचायत की शुरुआत.
2026-2030		• अमेरिका द्वारा वेनेजुअला के राष्ट्रपति का अपहरण, ईरान पर आक्रमण और कई देशों के व्यापार पर कर-नीति द्वारा नियंत्रण		• ईरान की ‘वितरित सत्ता’ जैसी और इससे मिलती-जुलती सुरक्षा-प्रतिरक्षा व्यवस्था, जिसे ‘मोजैक’ जैसा कहा जाता है और जिसके आगे अमेरिका के आक्रामक हथियारों का जखीरा नाकाम हो रहा है.

अमेरिका-ईरान युद्ध

-अविनाश झा

कई महीनों तक ईरान के इर्द-गिर्द विशाल युद्ध पोतों और विध्वंसक विमानों का घेरा बनाने के बाद अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त रूप से धावा बोल दिया। ईरान के लिए यह अपने अस्तित्व की लड़ाई है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिम ने जनतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर एक विश्वव्यापी व्यवस्था गढ़ी थी। पिछले वर्षों में इस व्यवस्था का औपनिवेशिक आधार पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। इस खुलासे के बाद पश्चिमी शक्तियां खुले आम हत्या, अपहरण और जनसंहार की नीति अपना रही है।

उन्होंने देशों और लोगों के बीच संवाद की प्रक्रियाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने एक वर्ष के भीतर छलपूर्वक दो बार ईरान पर संवाद के दौरान ही हमला बोला।

इस युद्ध ने संवाद की जरूरत को और रेखांकित किया है। पश्चिम से इतर जो दुनिया है वो दरअसल कई दुनियाओं से बना विश्व है। ऐसी दुनिया में शांति को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के अलावा मनुष्य समाज के लिए कोई विकल्प नहीं है।

साम्राज्य का ताना-बना बिखर रहा है जिससे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का रास्ता आसान होता जाएगा। भले ही साम्राज्य का विनाश हिंसात्मक कार्यवाहियों से मुक्त नहीं रहेगा।

ईरान इस साम्राज्यवादी ताक़त का सामना कर रहा है। कुछ दिनों में ही पश्चिम एशिया की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन आ गए हैं। ईरान के शक्ति के स्रोत ईरानी सभ्यता और शिया इस्लाम में देखे जा सकते हैं। ईरान के नेता, मंत्री और उच्च पदधारी विद्वान, दार्शनिक और न्यायविद इत्यादि हैं। इसके विपरीत अमेरिका और पश्चिम के नेता क्रय-विक्रय और लेन-देन के उस्ताद माने जाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता से अनुकरणीय व्यवहार की अपेक्षा रहती है। ईरान कभी पहले आक्रमण नहीं करता और अपने वादों से मुकरता नहीं है। पश्चिम के देशों के लिए अपने किए गए वादों से मुकरना उनकी मुख्य कार्यपद्धति बन गई है।

भारत को पश्चिम एशिया में अवस्थित कई दुनियाओं से एक नया संवाद स्थापित करना है। उपनिवेशवाद के विरोध से आगे जाकर भाईचारे को स्थापित करना है। भारतीय सभ्यता और ईरानी सभ्यता और उनके शक्ति के स्रोतों को लेकर एक गहन संवाद की जरूरत है जो कि आधुनिक समय में तो नहीं हो पाया है।

●

खाड़ी युद्ध में ईरानी गार्ड से क्या सीखें?

-गिरीश सहस्रबुद्धे

वर्त्तमान खाड़ी युद्ध में ईरान ने हमलावर अमेरिका-इज़राइल के सामने जो आवाहन खड़ा किया है, उसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है. खासकर एशिया के देशों के आम लोगों में. **ईरान की संप्रभुता बनी रहे यह हर दृष्टि से इन देशों के बहुजनों के हित में है.** इसे अभी तक बनाए रखने में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की भूमिका अहम् रही है. अपनी वित्तीय और कृत्रिम-प्रज्ञा-युक्त सैनिकी प्रौद्योगिकी की भयप्रद ताकत के दम्भ में चूर अमरीकी साम्राज्यवाद के विनाशकारी हमलों का गार्ड द्वारा किया जा रहा सामना किसी भी प्रस्थापित सैनिकी कसौटी पर बेहद आश्चर्यजनक और अनपेक्षित माना जा रहा है. शायद इसीलिए ईरान की इस काबिलियत को समझने के लिए **कई तर्क बहस में आगे आ रहे हैं. इनमें शिया धर्म, ईरानी सभ्यता की विरासत, आधुनिक सभ्यता का कमजोर मूलाधार, व्यावसायिक व्यवस्थाओं की कमजोरियां, गार्ड की रणनीति, इत्यादि कारक सामने आये हैं. हम सिर्फ इनमें से आखिरी दो पर मिली-जुली बात मोटे तौर पर रखेंगे. इसलिए नहीं कि अन्य कारक महत्वहीन हैं, बल्कि इसलिए कि इसमें वितरित बनाम केंद्रीकृत के टकराव का एक निश्चित आयाम उजागर होता है, जो 'बहुजन स्वराज' के परिप्रेक्ष्य में अपना महत्व रखता है.**

महत्वपूर्ण जानकारी : गार्ड ईरान के संविधान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आइ.आर.जी.सी.) के नाम से जाना जाता है. गार्ड की स्थापना 1979 की इस्लामी क्रान्ति के बाद अयातुल्ला रुहोल्ला खुमैनी द्वारा की गई थी. जहाँ ईरानी सेना देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए है, गार्ड का उद्देश्य इस्लामी क्रान्ति की अखण्डता बनाए रखना है. गार्ड के प्रमुख कमांडर की नियुक्ति ईरान के सर्वोच्च नेता करते हैं. मुहम्मद अली जाफरी 2007 से 2019 के बीच गार्ड के प्रमुख कमांडर रहे. देशों के प्रमुख नेताओं की हत्या

करने की अमेरिका की ज्ञात नीति के जवाब में इन्होंने अपने कार्यकाल में गार्ड के लिए एक प्रभावी रणनीतिक प्रणाली गढ़ी. **यह प्रणाली देफा-ए मोज़ैकी – यानी, मोज़ैक सुरक्षा – के नाम से जानी जाती है. छोटे-छोटे रंगीन टुकड़ों को जोड़ कर बनी कलाकृति को मोज़ैक-कला कहते हैं.**

खाड़ी युद्ध की शुरुआत में दो घटनाएं लगभग एक साथ घटीं. एक, चौबीस घंटों में 1000 मिसाइल ईरान पर दागे गये व ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामीनी की अन्य अनेक अग्रणी नेताओं के साथ हत्या कर दी गई. और दो, प्रतिदिन होर्मुज़ जलसन्धि से गुजरने वाले **तेलवाहक** जहाज़ों का बीमा करनेवाली, तथा इस बीमे की गारन्टी देने वाली कंपनियों ने बहत्तर घंटो का नोटिस देकर बीमा हटा लिया. पहली घटना के जवाब में गार्ड ने अपनी मोज़ैक सुरक्षा प्रणाली को तुरंत कार्यान्वित किया. दूसरी के परिणामावश होर्मुज़ जलसन्धि से गुजरने वाला दुनिया का 20% तेल व्यापार ठप हो गया.

मोज़ैक सुरक्षा प्रणाली की सबसे अहम् बात यह है कि इसके अंतर्गत ईरान के तीस प्रान्त और इकतीसवें तेहेरान की आइ.आर.जी.सी. इकाइयां स्वायत्त रूप में कार्य करना शुरू कर देती हैं. इसका अर्थ यह है कि हर सामरिक दृष्टि से, मतलब शस्त्र, ड्रोन, मिसाइल, सैनिक बल, सामरिक ज्ञान सभी मामलों में हर इकाई स्वयंपूर्ण है. इसके अलावा युद्ध के विषय में किसी केंद्रीय सहमति या निर्देश के बिना सब अपना-अपना निर्णय कर सकते हैं. केंद्रीय नेतृत्व का अभाव कोई कमजोरी पैदा नहीं करता. यह कोई दिमागी, या कागजी तर्क नहीं है. वर्त्तमान युद्ध में अमेरिका-इज़राइल द्वारा कई बड़े केंद्रीय नेताओं की एक के बाद एक हत्या के बावजूद लड़ते रहने की ईरान की ताकत में कोई घटौती अभी तक देखने में नहीं आई. न अभी तक कोई ऐसी घटना सामने आई है, जो गार्ड की स्वायत्त इकाइयों के बीच किसी तनाव या मनमुटाव का संदेह पैदा करे. लगता तो यह है कि ये सारी इकाइयां किन्हीं अर्थों में एक दूसरे की स्वायत्तता को ताकत और बढ़ावा दे रही हैं.

दुश्मन आज तक ईरान भर में फैले आठ-दस हजार स्थानों पर मिसाइल दाग चुका है, और बम गिरा चुका है, लेकिन आज तक खाड़ी में तेल यातायात फिर से शुरू करवा पाने में असफल है. यह भुलाया न जाय कि खाड़ी के पश्चिम किनारे के अरब देशों में स्थायी सैनिक बल कायम करने के पीछे अमेरिका और उसके मित्र देशों का प्रथम उद्देश्य हमेशा से तेल यातायात बेरोक-टोक हर समय चलता रहे, यह रहा है. इस युद्ध ने तो चलता यातायात ठप करवा दिया जो फिर शुरू नहीं हो पाया है. इसका कारण गार्ड की मोज़ैक प्रणाली की ताकत और व्यावसायिक बीमा व्यवस्थाओं की निर्णय लेने की कमजोरियां इनके एकत्रित प्रभाव में है. जहाँ एक तरफ गार्ड की स्वायत्त इकाइयों ने खाड़ी के पूर्वी किनारे से जहाज़ों पर मिसाइल का खतरा बनाए रखा है, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन या बीमा कंपनियों के एजेंट अब किसी एक केंद्र से बातचीत चलाकर ये खतरा घटा नहीं सकते. परिणाम यह है कि वास्तव में कुछ ही तेल जहाज़ों पर मिसाइल हमला, और बिना समुद्र में विस्फोटक माइनें लगाए भी, आइ.आर.जी.सी. बीमा कंपनियों की नज़र में पर्याप्त जोखिम का आभास बनाए रखने में कामयाब है. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य बीमा प्रक्रिया कायम कराने में छ: से अट्ठारह महीने तक लग सकते हैं. यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा तेल जहाज़ों को नौसेना की सुरक्षा देने और बीमा गारण्टी के लिए अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम को जिम्मेदारी देने के बावजूद स्थिति ज्यों कि त्यों बनी हुई है. जो जहाज होर्मुज़ से निकल पाए हैं वे सिर्फ ईरान की अनुमति से ही निकले हैं.

मौलिक बात : अब इस पूरी प्रक्रिया और घटनाक्रम में युद्ध के परिवेश को थोड़ा अलग हटा कर मौलिक बातों पर ध्यान दें. एक तरफ आधुनिक केंद्रीकृत प्रबंधन या व्यावसायिक निर्णय व्यवस्थाएं है. दूसरी तरफ वितरित स्वायत्त इकाइयों की मोज़ैक. इनके आतंरिक और आपसी व्यवहारों पर ध्यान दें. अब कल्पना करें, ऐसी सामाजिक इकाइयों की जो, गार्ड की इकतीस इकाइयों की ही तरह, संसाधनों के विषय में स्वयंपूर्ण हैं, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र और सक्षम हैं, जिनके पास अपना ज्ञान है, और जिनके आपसी व्यवहार एक किस्म के किसी स्वस्थ उद्देश्य से प्रेरित हैं. अब ईरानी युद्ध का अनुभव यह कहता है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वित्त, कृत्रिम-प्रज्ञा-प्रौद्योगिकी इत्यादि हथियारों की केंद्रीकृत व्यवस्थाओं की ताक़त के सामने ऐसी सामाजिक इकाइयाँ कमजोर ही हैं बल्कि, **देश की खुशहाली बहुजन स्वराज जैसे स्वस्थ उद्देश्य से प्रेरित बहुजन समाज की ऐसी ही स्वायत्त इकाइयों के मोज़ैक, या तानेबाने की कल्पना कर पाने में है.**

●

युद्ध आधारित सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ एक कविता

भले मुझे निष्कासित कर दो
इस मुल्क, इस दुनिया-जहान से
लेकिन मैं एक अपराध करना चाहता हूँ.
मैं चाहता हूँ,
बग़ैर हथियारों वाली एक दुनिया.

मैं चाहता हूँ,
हज़रत नूह की तरह मैं भी एक नाव बनाऊँ
दुनिया के तमाम हथियार भर दूँ उसमें
और बहा दूँ किसी बरमूड़ा ट्राइंगल की जानिब
मैं बेदख़ल कर देना चाहता हूँ.

दुनिया भर की तमाम पुलिस फ़ोर्स को
छीन लेना चाहता हूँ फ़ौजियों के मेडल
जो सरहदों पर किन्हीं के ख़ून का हिसाब हैं
मैं सरहदों को मिटा देना चाहता हूँ

या कि, वहाँ बिठा देना चाहता हूँ,
फ़ौजियों की जगह दीवानों को,
मीराँ को, सूर, कबीर, ख़ुसरो, फ़रीद,
मीर, ग़ालिब, फ़ैज़, जालिब और निदा को

इतिहास की किताबों से पोंछ देना चाहता हूँ
जीत की गाथाएँ,
हार की बेचैनियाँ,
ध्वस्त कर देना चाहता हूँ
क़िलों, महलों में टँगे जंग के प्रतीक-चिह्न.

संग्रहालयों में रखे हथियारों की जगह रख देना चाहता हूँ,
दुनिया भर के प्रेम-पत्र.

मैं लौट जाना चाहता हूँ हज़ारों साल पीछे
और मिटा देना चाहता हूँ,
तमाम धर्मग्रंथों से युद्ध के क़िस्से,
छीन लेना चाहता हूँ राम के हाथ से धनुष.
राजाओं, शहंशाहों के हाथ से तलवार
मिटा देना चाहता हूँ कर्बला की इबारत.

मैं कुरुक्षेत्र, कर्बला और तमाम युद्धस्थलों को लिख देना चाहता हूँ,
खेल के मैदान.
मैं कविताओं से सोख लेना चाहता हूँ वीर रस
एक कप चाय के बदले,
सूरज की तपिश को दे देना चाहता हूँ.

तमाम डिक्शनरियों के हिंसक शब्द
हिंसा के ख़िलाफ़ कहे और लिखे गए
मैं अपने हिंसक शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ !

स्रोत :
रचनाकार : फ़िरोज़ ख़ान
(रचनाकार की अन्य रचनायें और जानकारियां उपलब्ध नहीं की जा सकीं . -संपादक)
प्रकाशन : हिन्दवी से साभार

बौद्धिक सत्याग्रह की बुनियादी मान्यतायें

मनुष्य एक ज्ञान पुंज है. मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान से है. सभी मनुष्य ज्ञानी हैं. समाज में बसे ज्ञान की सभी धारायें बराबर के सम्मान की हक़दार हैं.

1. ज्ञान के क्षेत्र में श्रेणीबद्धता यानि ऊँच-नीच को अस्वीकार करना.
2. ज्ञान के किसी एक प्रकार को सबसे बढ़िया न मानना.
3. ज्ञान के किसी एक स्थान (जैसे विश्वविद्यालय) को सबसे अधिक महत्व न देना.
4. ज्ञान के निर्माण के किसी एक तरीके को सबसे सही न मानना.
5. ज्ञान के निजीकरण का विरोध करना.
6. ज्ञान के संगठन के विविध तरीके अपनाना.
7. मायावी (virtual) दुनिया की सीमाओं को पहचानना और उजागर करना.
8. लोकविद्या को विद्या का सम्मान देना.
9. लोकविद्या की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिये कार्य करना.
10. बहुजन-समाजों के ज्ञान के प्रति सम्मान की दृष्टि रखना.
11. शिक्षा में लोकविद्या के समावेश के तरीके विकसित करना.
12. कला को केवल मनोरंजन का साधन बनाने का विरोध करना.
13. ज्ञान के शोषण की व्यवस्थाओं को उजागर करना और इस शोषण के विरोध के संघर्षों में शामिल होना.
14. व्यापार और बाजार के मार्फत किसानों और कारीगरों की विद्या के शोषण का विरोध करना.
15. बहुजन-समाज अपनी विद्या का इस्तेमाल बिना रोक-टोक कर सके इसकी हिमायत करना.

बहुजन स्वराज पंचायत की मासिक बैठकें

अक्तूबर 2025 में विद्या आश्रम पर हुई बहुजन स्वराज पंचायत में भागीदार व्यक्तियों ने तय किया कि हर महीने में एक बैठक की जानी चाहिए ताकि बहुजन स्वराज के विचार को गढ़ने में कदम आगे बढ़ाये जा सकें. रामजनम, फ़ज़लुर्रहमान अंसारी और लक्ष्मण प्रसाद की सदारत में दिसंबर 2025 से प्रत्येक महीने की 15 तारीख पर ये बैठकें हो रही हैं. ये बैठकें ऑनलाइन यानि ज़ूम पर होती हैं और अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं. इन बैठकों का संक्षेप में एक विवरण यहाँ प्रस्तुत है. इन सभी बैठकों की रेकार्डिंग और शब्दांकन के लिंक भी दिए गए हैं.

1. पहली बैठक 15 दिसंबर 2025 को हुई. **विषय था 'बहुजन समाज की शक्ति के स्रोत उजागर करने मे साहित्य और कला की भूमिका'. मुख्य वक्ता के रूप में बहुजन के पक्षधर हिंदी के कथाकार, 'गाँव के लोग' पत्रिका के संपादक और अगोरा प्रकाशन के रामजी यादव आमंत्रित थे.** इस बैठक का विडियो रेकार्डिंग, शब्दांकन इस लिंक पर देख सकते हैं:
   https://drive.google.com/drive/folders/11lUcxb_aUKV3y9oTbJ1S8NTQm9GGxF3k?usp=sharing
2. गुरुवार, दि. 15 जनवरी 2026 को शाम 7.00 बजे बहुजन स्वराज पंचायत की तीसरी मासिक ऑन लाइन बैठक विषय था **'बहुजन हिताय उद्योग नीति क्या हो?'** इस संवाद में प्रमुख वक्ता अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बंगलुरु के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक अमित बसोले ने विस्तार से उद्योगनीति के विविध पहलुओं को सामने रखा. इस बैठक का विडियो रेकार्डिंग, शब्दांकन इस लिंक पर देख सकते हैं:
   https://drive.google.com/drive/folders/1zhB02M8WUIbkivsUxMg2ZRTPGt7xQUHs?usp=sharing
3. बहुजन स्वराज पंचायत की तीसरी मासिक ऑन लाइन बैठक 15 फरवरी 2026 को हुई, जिसका विषय था बैठक '**बौद्धिक सत्याग्रह - ज्ञान के क्षेत्र मे बहुजन का दखल**' इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच कृषि क्षेत्र में हुए समझौते के चलते बहुजन का विस्थापन और उजाड़ तथा विश्वविद्यालयों में बहुजन के साथ हो रहे शोषण और भेदभाव से मुकाबले के रास्ते पर विचार होना था. विषय पर बोलने के लिए दो वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था. **पहले वक्ता के रूप में गाँव के लोगों की आवाज़ में जान फूंकने वाली पत्रकार, 'गाँव के लोग' वेब साईट पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्थापन की विस्तृत रिपोर्टिंग और *'आफत में गाँव'* पुस्तक (अगोरा प्रकाशन, वाराणसी) की लेखिका अपर्णा जी और दूसरे वक्ता के रूप में बीएचयू से समाजशास्त्र में पीएचडी हासिल तथा अपने छात्र जीवन से ही बहुजन के लिए बराबरी के मुखर प्रवक्ता रहे डॉ. राहुल राजभर, जो अब समानता के लिए और शोषण के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में सक्रिय है.** इस बैठक का विडियो रेकार्डिंग, शब्दांकन इस लिंक पर देख सकते हैं:
   https://drive.google.com/drive/folders/151-XLzd0R1GC-6N911hXEb-j02kpMFz9?usp=sharing
4. 15 मार्च 2026 की चौथी बैठक हुई. **वक्ता : किसान नेता विजय जावंधिया 'कृषि क्षेत्र में अमेरिका भारत समझौता' और दूसरे वक्ता : लोकविद्या जन आन्दोलन के गिरीश सहस्रबुद्धे ने अमेरिका इजराइल एवं ईरान युद्ध'** अपने-अपने विषयों के विविध आयामों को रखा. इस बैठक का विडियो रेकार्डिंग, शब्दांकन इस लिंक पर देख सकते हैं:
   https://drive.google.com/drive/folders/1S8f6YmFTL8CgEK-Lw3_RbwcCs-CxUGCz?usp=sharing

●

बहुजन के पास समाज में जन्मा और संवर्धित होता ज्ञान
संवेदना और विवेक से गर्भित होता है;
सत्य और न्याय के नजदीक होता है.
ज्ञान को धार्मिक मठों, विश्वविद्यालय व कालेजों की दीवारों, पोथियों व लाइब्रेरियों,
कम्प्यूटर व इन्टरनेट की कैद से मुक्त कर समाज के बीच पनपने और बढ़ने दें.
मनुष्य, समाज और देश के लिए सत्य के पथ तभी खुलेंगे.

●

बहुजन हिताय उद्योग नीति के लिए विचार बिंदु

बहुजन स्वराज पंचायत की मासिक चिंतन बैठक के लिए बना आधार परचा

औद्योगिक युग में साम्राज्यवादी देशों ने जब कृषि को उद्योगों के मातहत बनाने और छोटे उद्योगों की जगह बड़े उद्योगों और मशीनीकरण बढाने की नीतियों को थोंपा और इसे ही 'विकास' का रास्ता घोषित किया तब से भारत जैसे देशों में बहुजन की तबाही का नया दौर शुरू हो गया. अब 21वीं सदी के व्यापारिक युग में ये विकराल हो चला है. ऐसे में बहुजन हिताय उद्योग नीति कैसी होनी चाहिए इस पर चिंतन आवश्यक है. इस बैठक में विषय को खोलने और वार्ता को सटीक बनाने के लिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द हम इस वार्ता को चलाएंगे.

मुद्दा :

आज़ाद भारत में उद्योग नीति का अर्थ बड़े उद्योगों को बढ़ाने का रहा. इसके चलते बहुजन के सामने कम रोज़गार, कम आमदनी, ज़बरन विस्थापन, पक्षपातपूर्ण बाज़ार, सार्वजनिक जीवन में मजदूर व स्त्रियों की अप्रतिष्ठा और इनके विरोधी माहौल तथा पर्यावरण का अभूतपूर्ण विनाश हुआ. यह तर्क दिया था कि सामाजिक असमानता में कमी आएगी पर ऐसा नहीं हुआ.

विरोध की धाराएँ :

शुरुआत में गाँधीवादी विचारधारा के अंतर्गत बड़ी मशीन(बड़ी पूँजी) बनाम छोटी मशीन(छोटी पूँजी) और समाजवादी विचार के तहत उद्योगों के प्रबंधन और मुनाफे में मज़दूरों की हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर बहस और संघर्ष के कार्यक्रम चले और 20वीं के अंत में विस्थापन विरोध और पर्यावरण विनाश के मुद्दे संघर्ष के आधार बने. अब सूचना युग में जब व्यापार और बाज़ार का प्रबंधन इन्टरनेट से नियंत्रित किया जाने लगा है; तब से पूरी राजनीति और राजसत्ता की सारी व्यवस्थाएं कुछ मुट्ठीभर 'विशेषजन' के हित वाले उद्योग और इस व्यापार नीति को ही 'विकास' घोषित कर चुके हैं. इसका मुकाबला स्थानीय स्वायत्तता औरन सत्ता के वितरित प्रकार विरोध और नवरचना के मौके देते हैं.

बहुजन के हित में नीतिगत मांगें :

बहुजन स्वराज पंचायत के सामने बहुजन हिताय उद्योग नीति का चित्र क्या बनता है? कुछ बिंदु विचार के लिए इस प्रकार हैं—

- ज़बरन विस्थापन बंद हो और स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने की नीति हो.
- जिसको जो काम आता है उसके आधार पर उनकी सम्मानित जीविका सुनिश्चित हो. यानि हर वयस्क स्त्री/पुरुष को उसके ज्ञान(लोकविद्या) के बल पर रोज़गार की व्यवस्था व नीति का निर्माण हो.
- हर परिवार को सरकारी कर्मचारी के बराबर आमदनी सुनिश्चित करने की नीति बने.
- स्थानीय बाजारों में स्थानीय किसान-कारीगरों को और उनके उत्पादनों को प्राथमिकता/वरीयता मिले. इन बाज़ारों के प्रबंधन और निर्णय समितियों में स्थानीय किसान-कारीगरों की उपस्थिति व सहमति अनिवार्य हो.
- स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के निर्णयों में स्थानीय लोगों की राय को वरीयता हो.
- असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले बहुजन को 'मजदूर' कहा जाता है, इन सभी को 'कारीगर' कहा जाये. ये सब मात्र श्रमिक नहीं होते, बल्कि अपने ज्ञान, हुनर, शिल्प, कौशल और विरासत पर खड़े होते हैं.

वाराणसी ज्ञान पंचायत के लिए लोकविद्या जन आन्दोलन, भारतीय किसान यूनियन, स्वराज अभियान, बुनकर साझा मंच, और कारीगर नजरिया द्वारा संयुक्तरूप से संयोजित.

संपर्क : चित्रा सहस्रबुद्धे (9838944822), लक्ष्मण प्रसाद (9026219913), रामजनम, (8765619982), फ़ज़लुर्रहमान अंसारी (7905245553), प्रेमलता सिंह
पता : विद्या आश्रम, सा 10/82 अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-221007

<u>वाराणसी के ज्ञानी निवासियों से</u>

किसान, कारीगर, आदिवासी, लोक-कलाकार,
महिलाएं व ठेला-पटरी-गुमटी के दुकानदार
और सेवा-मरम्मत करने वाले सभी परिवार,
ये सब हैं लोकविद्या के ज्ञानी और जानकार.

जब माना जायेगा लोकविद्या को भी ज्ञान,
और मिलेगा पढ़े-लिखे लोगों के ज्ञान-सा सम्मान
जब होगी इनकीआमदनी भी सरकारी कर्मचारीसी,
तभी मिलेगी इस मुल्क को सच्ची आज़ादी.